एक ऐसा लक्ष्य निर्धारित करें जो आपको, सुबह बिस्तर से उठने पर मजबूर कर दें।

तेवर वही, अंदाज नया .....!
साप्ताहिक

उज्जैन टाइम्स

डाक रजिस्ट्रेशन नं. मालवा डिवीजन-
L2/65/RNP/397/2024-2026

प्रधान सम्पादक : मनमोहन शर्मा

RNI No. 7583/61

● वर्ष : 63, अंक : 39 ● उज्जैन, मंगलवार दिनांक 25-06-2024 से 01-07-2024 तक ● पृष्ठ : 08 ● मूल्य : 2 रुपये

इस्लाम को कहा-अलविदा

अनिकेत ने फराह को सोनाक्षी के रूप में अपनी पत्नी स्वीकार किया।

हिन्दू संस्कृति के आचरण उसे सनातन में खींच लाये

उज्जैन। फरहानाज खान जब हिन्दू युवक अनिकेत के संपर्क में आई। जीवन को देखने का उसका नजरिया ही बदल गया। वहीं, हिन्दू सनातन धर्म में

स्त्री के प्रति आदर-सम्मान एवं किसी बंधन में जबरन नहीं रखने के साथ पूजा स्थल में भी बराबर से मान देने जैसे अनेक हिन्दू संस्कृति के आचरण उसे सनातन की ओर गहराई से खींच लाई। जिसके बाद उज्जैन में इस तलाकशुदा मुस्लिम महिला ने अपनी 10 वर्षीय बेटी के साथ स्वयं को सनातन धर्म के लिए समर्पित कर दिया।

महिला ने सनातन धर्म की विवाह पद्धति एवं अन्य रीति-रिवाज के अनुसार रविवार को हिन्दू युवक अनिकेत से विधि पूर्वक विवाह कर लिया है। पूजा उज्जैन के मंगलनाथ मंदिर स्थित सुमन आश्रम में विधि विधान गौरी-गणेश वंदन से आरंभ होकर यज्ञ के समापन एवं पूर्णाहुति के साथ सम्पन्न हुई। इसी के साथ फरहानाज खान को अब नया नाम सोनाक्षी चौबे के रूप में नई पहचान मिली है। वहीं, उनकी दस वर्षीय बेटी जारा का नया नाम जान्हवी रखा गया है। अपनी नई पहचान के साथ सोनाक्षी चौबे का विवाह होने के पश्चात कहना रहा कि वह पिछले तीन सालों से हिन्दू विवाह पद्धति के अनुसार अनिकेत से विवाह करना चाहती थी। लेकिन इसके लिए संयोग नहीं बन पा रहा था, पर जब उन्होंने विवाह के लिए मोनी तीर्थ आश्रम पर संपर्क किया और महाराज से विवाह करने की अनुमति मांगी, इसके लिए आवश्यक विधि करवाने के लिए आग्रह किया तो स्वामी जी ने इसे सहज स्वीकार्य कर लिया । इसके बाद उसने उज्जैन के मंगलनाथ मंदिर के समीप स्थिति मौन तीर्थ में रविवार को सनातन धर्म अपना लिया और मौन तीर्थ के महामंडलेश्वर सुमनानंद ने फरहानाज खान को नया हिन्दू नाम देकर एक नई पहचान दी। फिर हिन्दू धर्म अपनाने के बाद सोनाक्षी ने युवक अनिकेत के साथ विवाह कर लिया।

इस संबंध में महामण्डलेश्वर स्वामी सुमनआनंद गिरी महाराज का कहना है कि सनातन में सभी के लिए द्वार खुले हुए हैं। सनातन हिन्दू धर्म वास्तव में एक संस्कार है, जोकि विज्ञान सम्मत है, इसलिए आज पूरी दुनिया इसके महत्व को स्वीकार कर रही है। उन्होंने कहा कि उक्त महिला सोनाक्षी और युवक अनिकेत दोनों ही उज्जैन के ही रहने वाले हैं। महिला का कई साल पहले निकाह हुआ था, किंतु वह चल नहीं सका। इस बीच उसकी बेटी जो अब तक दस साल की हो गई। फिर कुछ साल पहले ही उसका तलाक हो गया और वह अपनी बेटी के साथ अकेली ही रह रही थीं। इसी दौरान उनका अनिकेत चौबे से संपर्क आया एवं दोनों ही एक-दूसरे का हर बात में सम्मान करते देखे गए। अब अनिकेत ने फराह को सोनाक्षी के रूप में अपनी पत्नी और उसकी बेटी को अपनी पुत्री स्वीकार कर लिया है। विवाह के संबंध में इन दोनों ने ही पूरी प्रक्रिया के लिए नोटरी करा कर रजिस्टर कागज भी हासिल कर लिए हैं।

सम्पादकीय

गंभीर पेयजल समस्या

शहरी नियोजन की चपेट में आकर बहुत सारे प्राकृतिक जलाशय पहले ही अपना अस्तित्व खो चुके हैं, अब बचेखुचे संरक्षित जलाशयों पर जलवायु परिवर्तन का प्रकोप पड़ना शुरू हो चुका है। केंद्रीय जल आयोग की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश के डेढ़ सौ प्रमुख जलाशयों का स्तर घट कर महज इक्कीस फीसद रह गया है। भीषण गर्मी का असर सबसे अधिक दक्षिण भारत के जलाशयों पर देखा गया है, जहां बयालीस जलाशय हैं और उनमें जल की मात्रा घट कर सोलह फीसद तक रह गई है।

हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और पंजाब के दस जलाशयों में उनकी कुल क्षमता का अट्ठाईस फीसद जल रह गया है।

यही हाल पूर्वोत्तर के तेईस जलाशयों का है, जिनमें उनकी कुल भंडारण क्षमता का करीब बीस फीसद पानी रह गया है।

इसे लेकर जल आयोग की चिंता स्वाभाविक है। पहले ही बरसात कम होने की वजह से इन जलाशयों का पुनर्भरण संतोषजनक स्तर तक नहीं पहुंच पाया था, फिर पहाड़ों पर बर्फ कम गिरने के कारण पहाड़ी इलाकों के जलाशयों में पानी का स्तर लगातार घट रहा है।

प्राकृतिक जलाशय अनेक शहरों के लिए पेयजल उपलब्ध कराने का प्रमुख स्रोत हैं। मगर समुचित रखरखाव और उनके जलस्रोतों का संरक्षण न हो पाने की वजह से उनमें बरसात का पानी भी समुचित रूप में नहीं पहुंच पाता। जलाशयों में बरसात का पानी ऊंचे इलाकों से पहुंचता है, मगर जब वहां बस्तियां बस जाती हैं, तो उनका जलस्रोत बाधित होता है। बहुत सारे जलाशयों का जल स्तर इसलिए भी घट रहा है। दूसरी सबसे बड़ी वजह पिछले कुछ वर्षों से तापमान में लगातार वृद्धि और बरसात का असंतुलित होना भी है।

गर्मी की अवधि लंबी होने से पेयजल और दूसरे उपयोग के लिए पानी की खपत बढ़ रही है। ऐसे में जलाशयों का स्तर घटते जाने से उन पर निर्भर शहरों और बस्तियों में जलसंकट बढ़ने की आशंका गहराने लगी है।

लंबे समय से सलाह दी जाती रही है कि प्राकृतिक जलाशयों के रखरखाव और उनके जलस्रोतों को अबाध बनाए रखने की योजनाएं बनानी होंगी। बरसात का पानी उन तक पहुंचता रहे और उनमें गाद वगैरह की सफाई होती रहे, तभी उनके पुनर्भरण की संभावना बनेगी।

सावरेन क्रेडिट रेटिंग को अपग्रेड करने पर हो रहा है विचार

वैश्विक स्तर पर विभिन्न देशों की सावरेन क्रेडिट रेटिंग पर कार्य कर रही संस्था स्टैंडर्ड एंड पूअर ने हाल ही में भारतीय अर्थव्यवस्था का आंकलन करते हुए भारत के सम्बंध में अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक किया है एवं कहा है कि वह भारत की सावरेन क्रेडिट रेटिंग को अपग्रेड करने के उद्देश्य से भारत के आर्थिक विकास सम्बंधी विभिन्न पैमानों का एवं भारत के राजकोषीय घाटे से सम्बंधित आंकड़ों का लगातार अध्ययन एवं विश्लेषण कर रहा है। यदि उक्त दोनों क्षेत्रों में लगातार सुधार दिखाई देता है तो भारत की सावरेन क्रेडिट रेटिंग को अपग्रेड किया जा सकता है। वर्तमान में भारत की सावरेन क्रेडिट रेटिंग BBB- है, जो निवेश के लिए सबसे कम रेटिंग की श्रेणी में गिनी जाती है।

किसी भी देश की सावरेन क्रेडिट रेटिंग को यदि अपग्रेड किया जाता है तो इससे उस देश में विदेशी निवेश बढ़ने लगते हैं क्योंकि निवेशकों का इन देशों में पूंजी निवेश तुलनात्मक रूप से सुरक्षित माना जाता है। साथ ही, अच्छी सावरेन क्रेडिट रेटिंग प्राप्त देशों की कम्पनियों को अन्य देशों में पूंजी उगाहना न केवल आसान होता है बल्कि इस प्रकार लिए जाने वाले ऋण पर ब्याज की राशि भी कम देनी होती है। किसी भी देश की जितनी अच्छी सावरेन क्रेडिट रेटिंग होती है उस देश की कम्पनियों को कम से कम ब्याज दरों पर ऋण उगाहने में आसानी होती है। भारत में हाल ही में केंद्र में नई सरकार के गठन सम्बंधी प्रक्रिया सम्पन्न हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी सहित केंद्रीय मंत्रीमंडल के समस्त सदस्यों को विभागों का आबंटन भी किया जा चुका है। केंद्र सरकार द्वारा पिछले दस वर्षों के दौरान लिए गए आर्थिक निर्णयों का भरपूर लाभ देश को मिला है। इससे देश के आर्थिक विकास को गति मिली है एवं आज भारत, विश्व में सबसे तेज गति से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था बन गया है। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले नागरिकों की संख्या में अपार कमी दृष्टिगोचर है। देश में बहुत बड़े स्तर पर वित्तीय समावेशन हुआ है, जनधन योजना के अंतर्गत 50 करोड़ से अधिक बैंक बचत खाते खोले जा चुके हैं एवं इन बचत खातों में आज लगभग 2.50 लाख करोड़ रुपए की राशि जमा है, इस राशि का उपयोग देश के आर्थिक विकास के लिए किया जा रहा है। रोजगार के नए अवसर भारी संख्या में निर्मित हुए हैं। देश में प्रति व्यक्ति आय भी बढ़कर लगभग 2200 अमेरिकी डॉलर प्रतिवर्ष तक पहुंच गई है। देश के कुछ राज्यों में तो किसानों की आय दुगने से भी अधिक हो गई है। भारत में विदेशी निवेश भारी मात्रा में होने लगा है एवं बहुराष्ट्रीय कम्पनियां अपनी विनिर्माण इकाईयों की स्थापना भारत में ही करने लगी हैं। इससे देश में विनिर्माण इकाईयों (उद्योग क्षेत्र) की विकास दर 8-9 प्रतिशत के पास पहुंच गई है। मंदिर की अर्थव्यवस्था एवं लगातार तेज गति से आगे बढ़ रहे धार्मिक पर्यटन के चलते भारत में आर्थिक विकास की दर वित्तीय वर्ष 2023-24 में 8 प्रतिशत से भी अधिक रही है।

भारत, अपने आर्थिक विकास की गति को और अधिक तेज करने के उद्देश्य से आधारभूत ढांचें को विकसित करने के लगातार प्रयास कर रहा है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में 7.5 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान देश के आधारभूत ढांचे को विकसित करने हेतु किया गया था, जिसे वित्तीय वर्ष 2023-24 में 33 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया था एवं वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए इसे और अधिक बढ़ाकर 11.11 लाख करोड़ रुपए का कर दिया गया है। आधारभूत ढांचे को विकसित करने से देश में उत्पादकता में सुधार हुआ है एवं विभिन्न उत्पादों की उत्पादन लागत में कमी आई है। जिससे, कई बहुराष्ट्रीय कम्पनियां अपनी विनिर्माण इकाईयों को भारत में स्थापित करने हेतु आकर्षित हुई हैं। स्टैंडर्ड एंड पूअर का तो यह भी कहना है कि भारत जिस प्रकार की आर्थिक नीतियों को लागू करते हुए आगे बढ़ रहा है और केंद्र में नई सरकार के आने के बाद से अब सम्भावनाएं बढ़ गई हैं कि भारत में आर्थिक सुधार कार्यक्रम बहुत तेजी के साथ किए जाएंगे इससे कुल मिलाकर भारत की आर्थिक विकास दर को लम्बे समय तक 8 प्रतिशत से ऊपर बनाए रखा जा सकता है। भारत ने अपने आर्थिक विकास की गति को तेज रखते हुए अपने राजकोषीय घाटे पर भी नियंत्रण स्थापित कर लिया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत का राजकोषीय घाटा 17 लाख 74 हजार करोड़ रुपए का रहा था जो वित्तीय वर्ष 2023-24 में घटकर 16 लाख 54 हजार करोड़ रुपए का रह गया है। यह राजकोषीय घाटा वित्तीय वर्ष 2022-23 में 5.8 प्रतिशत था जो वित्तीय वर्ष 2023-24 में घटकर 5.6 प्रतिशत रह गया है। भारत के राजकोषीय घाटे को वित्तीय वर्ष 2024-25 में 5.1 प्रतिशत एवं वित्तीय वर्ष 2025-26 में 4.5 प्रतिशत तक नीचे लाने के प्रयास केंद्र सरकार द्वारा सफलता पूर्वक किए जा रहे हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रान्स, जर्मनी जैसे विकसित देश भी अपने राजकोषीय घाटे को कम नहीं कर पा रहे हैं, परंतु भारत ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान यह बहुत बड़ी सफलता हासिल की है। सरकार का खर्च उसकी आय से अधिक होने पर इसे राजकोषीय घाटा कहा जाता है। केंद्र सरकार ने खर्च पर नियंत्रण किया है एवं अपनी आय के साधनों में अधिक वृद्धि की है। यह लम्बे समय में देश के आर्थिक स्वास्थ्य की दृष्टि से एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य उभरकर सामने आया है। भारत के कुछ राज्यों (पंजाब, पश्चिम बंगाल, केरल, आदि) में राजकोषीय घाटे को लेकर चिंता व्यक्त की जा रही है, परंतु केंद्र सरकार एवं कुछ अन्य राज्य (उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु आदि) जरूर अपने राजकोषीय घाटे को सफलता पूर्वक नियंत्रित कर पा रहे हैं। राजकोषीय घाटा मलेशिया, फिलिपीन, इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम जैसे देशों में 4 प्रतिशत से कम है जबकि भारत में केंद्र सरकार एवं समस्त राज्यों का कुल मिलाकर राजकोषीय घाटा 7.9 प्रतिशत है।

उक्त वर्णित समस्त देशों की सावरेन क्रेडिट रेटिंग BBB है जबकि भारत की सावरेन क्रेडिट रेटिंग BBB है। अतः भारत के कुछ राज्यों को तो अपने राजकोषीय घाटे को कम करने हेतु बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है।

राजकोषीय घाटे को कम करने में भारत को सफलता इसलिए भी मिली है कि देश 20 से अधिक करों को मिलाकर केवल एक कर प्रणाली, वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली, को सफलता पूर्वक लागू किया गया है। आज वस्तु एवं सेवा कर के रूप में भारत को औसत 1.75 लाख करोड़ रुपए की राशि प्रतिमाह अप्रत्यक्ष कर के रूप में प्राप्त हो रही है। साथ ही, प्रत्यक्ष कर के संग्रहण में भी 20 प्रतिशत की भारी भरकम वृद्धि परिलक्षित हुई है। भारत में बैंकिंग व्यवस्थाओं के डिजिटलीकरण को ग्रामीण इलाकों तक में लागू करने से भारतीय अर्थव्यवस्था का औपचारीकरण बहुत तेज गति से हुआ है, जिससे प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर संग्रहण में भारी भरकम वृद्धि हुई है। जबकि केंद्र सरकार एवं कुछ राज्य सरकारों ने अपने गैर योजना खर्च की मदों पर किए जाने वाले व्यय पर नियंत्रण करने में सफलता भी पाई है। इसके कारण राजकोषीय घाटे को लगातार प्रति वर्ष कम करने में सफलता मिलती दिखाई दे रही है।

कुल मिलाकर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न देशों की सावरेन क्रेडिट रेटिंग का आंकलन करने वाले विभिन्न संस्थान भारत की आर्थिक प्रगति को लेकर बहुत उत्साहित हैं एवं आर्थिक प्रगति के साथ साथ राजकोषीय घाटे को कम करते हुए भारत द्वारा जिस प्रकार अपनी वित्त व्यवस्था को नियंत्रण में रखने का काम सफलता पूर्वक किया जा रहा है, इससे यह संस्थान भारत की सावरेन क्रेडिट रेटिंग को अपग्रेड करने हेतु गम्भीरता से विचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्टैंडर्ड एंड पूअर ने तो घोषणा भी कर दी है कि आगे आने वाले दो वर्षों तक वह भारत की आर्थिक प्रगति, आधारभूत ढांचे को विकसित करने एवं राजकोषीय घाटे को कम करने सम्बंधी प्रयासों का गम्भीरता से विवेचन कर रहा है और बहुत सम्भव है कि वह आगामी दो वर्षों में भारत की सावरेन क्रेडिट रेटिंग को अपग्रेड कर सकने की स्थिति में आ जाए।

कलेक्टर मैडम, आप 'मेकअप' क्यों नहीं करती...?

मलप्पुरम की जिला कलेक्टर सुश्री रानी सोयामोई...कॉलेज के छात्रों से बातचीत करती हैं। उन्होंने कलाई घड़ी के अलावा कोई आभूषण नहीं पहना था।

सबसे ज्यादा छात्रों को आश्चर्य हुआ कि उन्होंने 'फेस पाउडर' का भी इस्तेमाल नहीं किया।

भाषण अंग्रेजी में था। उन्होंने केवल एक या दो मिनट ही बोला, लेकिन उनके शब्द दृढ़ संकल्प से भरे थे। फिर बच्चों ने कलेक्टर से कुछ सवाल पूछे।

प्रश्न-आपका नाम क्या है?

मेरा नाम रानी है, सोयामोई मेरा पारिवारिक नाम है। मैं झारखंड की मूल निवासी हूं।

...और कुछ पूछना है?

दर्शकों में से एक दुबली-पतली लड़की खड़ी हुई।

पूछो, बच्चे...

मैडम, आप मेकअप क्यों नहीं करतीं?

कलेक्टर का चेहरा अचानक पीला पड़ गया। उनके पतले माथे पर पसीना आ गया। उनके चेहरे की मुस्कान फीकी पड़ गई। दर्शक अचानक चुप हो गए। उन्होंने टेबल पर रखी पानी की बोतल खोली और थोड़ा पानी पिया। फिर उसने धीरे से छात्र को बैठने का इशारा किया।

फिर वह धीरे से बोलने लगी।

तुमने एक परेशान करने वाला सवाल पूछा है। यह ऐसा सवाल है जिसका जवाब एक शब्द में नहीं दिया जा सकता। मुझे जवाब में तुम्हें अपनी जीवन कहानी सुनानी है। मुझे बताओ कि क्या तुम मेरी कहानी के लिए अपने कीमती दस मिनट निकालने को तैयार हो?

तैयार...

मेरा जन्म झारखंड के एक आदिवासी इलाके में हुआ था। कलेक्टर ने रुककर दर्शकों की ओर देखा।

मेरा जन्म कोडरमा जिले के आदिवासी इलाके में एक छोटी सी झोपड़ी में हुआ था, जो मीका खदानों से भरा हुआ था।

मेरे पिता और माता खनिक थे। मेरे दो बड़े भाई और एक छोटी बहन थी। हम एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे जिसमें बारिश होने पर पानी टपकता था। मेरे माता-पिता कम वेतन पर खदानों में काम करते थे क्योंकि उन्हें कोई और काम नहीं मिल पाया था। यह बहुत गंदा काम था। जब मैं चार साल की थी, तब मेरे पिता, माता और दो भाई कई बीमारियों के कारण बिस्तर पर पड़े थे।

उस समय उन्हें यह नहीं पता था कि यह बीमारी खदानों में मौजूद घातक मीका धूल को अंदर लेने से होती है। जब मैं पाँच साल की थी, मेरे भाई बीमारी से मर गए। एक छोटी सी आह भरकर कलेक्टर ने बोलना बंद कर दिया और अपने रूमाल से अपनी आँखें पोंछ लीं।

ज़्यादातर दिनों में हमारा भोजन सादा पानी और एक या दो रोटियाँ हुआ करता था। मेरे दोनों भाई गंभीर बीमारी और भूख के कारण इस दुनिया से चले गए। मेरे गाँव में, डॉक्टर तो छोड़िए, स्कूल भी नहीं था। क्या आप ऐसे गाँव की कल्पना कर सकते हैं जहाँ स्कूल, अस्पताल या शौचालय न हो, बिजली न हो?

एक दिन मेरे पिता ने मेरा भूखा, चमड़ी और हड्डियों से लथपथ हाथ पकड़ा और मुझे टिन की चादरों से ढकी एक बड़ी खदान में ले गए। यह एक अभ्रक की खदान थी जिसने समय के साथ बदनामी हासिल कर ली थी। यह एक पुरानी खदान थी जिसे खोदा गया और खोदा गया, जो अंतहीन रूप से पाताल में फैली हुई थी। मेरा काम नीचे की छोटी-छोटी गुफाओं में रेंगना और अभ्रक अयस्क इकट्ठा करना था। यह केवल दस साल से कम उम्र के बच्चों के लिए ही संभव था। अपने जीवन में पहली बार, मैंने पेट भर रोटियाँ खाईं। लेकिन उस दिन मुझे उल्टी हो गई।

जिस समय मुझे प्रथम श्रेणी में होना चाहिए था, मैं अंधेरे कमरों में अभ्रक इकट्ठा कर रही थी, जहाँ मैं 'जहरीली धूल' में साँस ले रहा था।

कभी-कभार 'भूस्खलन' में दुर्भाग्यपूर्ण बच्चों का मर जाना असामान्य नहीं था। और कभी-कभी कुछ 'घातक बीमारियों' से भी मर जाते थे दिन में आठ घंटे काम करने के बाद, आप कम से कम एक बार के भोजन के लिए कमा पाते थे। मैं भूख और हर दिन जहरीली गैसों के साँस लेने के कारण दुबली और निर्जलित हो गई थी।

एक साल बाद मेरी बहन भी खदान में काम करने लगी। जैसे ही वे (पिता) थोड़े ठीक हुए, ऐसा समय आया कि मेरे पिता, माँ, बहन और मैं एक साथ काम करते थे और हम बिना भूख के रह सकते थे।

लेकिन किस्मत ने हमें दूसरे रूप में परेशान करना शुरू कर दिया था। एक दिन जब मैं तेज बुखार के कारण काम पर नहीं जा रही थी, अचानक बारिश हुई। खदान के नीचे काम करने वाले श्रमिकों पर खदान गिरने से सैकड़ों लोग मारे गए। उनमें मेरे पिता, माँ और बहन भी थे।

रानी की दोनों आँखों से आँसू बहने लगे। दर्शकों में हर कोई साँस लेना भी भूल गया। कई लोगों की आँखें आँसुओं से भर गईं। आपको याद रखना होगा कि मैं सिर्फ छह साल की थी। आखिरकार मैं सरकारी अगाती मंदिर पहुँची। वहाँ मेरी शिक्षा हुई। मैंने अपने गाँव से ही अपनी पहली अक्षर-पद्धति सीखी थी। आखिरकार यहाँ कलेक्टर आपके सामने हैं।

आप सोच रहे होंगे कि इसका और इस बात का क्या संबंध है? कि मैं मेकअप का इस्तेमाल नहीं करती। उसने दर्शकों की तरफ देखते हुए कहा।

अपनी शिक्षा के दौरान ही मुझे एहसास हुआ कि उन दिनों अँधेरे में रेंगते हुए मैंने जो सारा अभ्रक इकट्ठा किया था, उसका इस्तेमाल मेकअप उत्पादों में किया जा रहा था।

अभ्रक पहला प्रकार का मोती जैसा सिलिकेट खनिज है। कई बड़ी कॉस्मेटिक कंपनियों द्वारा पेश किए जाने वाले खनिज मेकअप में, आपकी त्वचा के लिए सबसे चमकीला रंग बहुरंगी अभ्रक से आता है, जिसे 20,000 छोटे बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर निकालते हैं।

गुलाब की कोमलता उनके जले हुए सपनों, उनके बिखरते जीवन और चट्टानों के बीच कुचले गए उनके मांस और खून के साथ आपके गालों पर फैलती है। खदानों से बच्चों के हाथों से उठाए गए लाखों डॉलर के अभ्रक का इस्तेमाल आज भी किया जाता है। हमारी सुंदरता को बढ़ाने के लिए। अब आप ही बताइए।

मैं अपने चेहरे पर मेकअप कैसे लगाऊं? मैं अपने भाइयों की याद में पेट भरकर कैसे खाऊं जो भूख से मर गए? मैं अपनी मां की याद में महंगे रेशमी कपड़े कैसे पहनूं जिन्होंने कभी फटे कपड़ों के बारे में सपने में भी नहीं सोचा था?

जब रानी चली गईं तो पूरा दर्शक अनजाने में ही खड़ा हो गया, उनके होठों पर हल्की मुस्कान थी, आँखों में आँसू पोंछे बिना, उनका सिर ऊँचा था।

(झारखंड में अभी भी उच्चतम गुणवत्ता वाला अभ्रक खनन किया जाता है। 20,000 से अधिक छोटे बच्चे स्कूल जाने के बिना वहां काम करते हैं। वे मर जाते हैं, कुछ भूस्खलन में और कुछ बीमारी से...)

कई साल बाद...वह महिला कलेक्टर, भारत गणराज्य की पहली नागरिक बनी महामहिम द्रौपदी मूर्ममु भारत गणराज्य की राष्ट्रपति!

योग पर सरल चिंतन, योग अर्थात् जुड़ना

1. जुड़ेंगे कब?

जब कहीं से छूटेंगे। किसी से छूटेंगे।

2. कहा से/कि स से छूटना है ?

दुखों से। जन्म से। सकाम प्रवृत्ति से। दोषों से। मिथ्या ज्ञान से। अज्ञान से। अविद्या से।

जब उक्त से छूटेंगे, तभी तो निम्न से जुड़ेंगे।

3. किससे जुड़ना है?

सुख से। शांति से। आनंद से। विवेक ज्ञान से। वैराग्य भाव से। क्रियात्मक योग अभ्यास से।

4. कैसे जुड़ेंगे?

अष्टांग योग से।

यम नियम के पालन से। आसन में स्थिरता से।

प्राणायाम की प्रक्रिया से।

प्रत्याहार की अभ्यास से।

धारणा पूर्वक ध्यान से।

क्रियात्मक योग से। (तप-स्वाध्याय-ईश्वर प्राणिधान से)

5. क्या प्राप्त होगी?

दुखों से मुक्ति।

शारीरिक स्वस्थता।

मानसिक प्रसन्नता।

बौद्धिक क्षमता।

कर्मों की कुशलता।

मन के विचारों पर निरोधता।

आत्मिक स्वरूपता।

परमात्मा के स्वरूप में मग्नता।

अर्थात्

समाधि प्राप्ति।

6. कब सब प्राप्त होगा?

जब साधक दीर्घ काल तक, निरंतर, श्रद्धा पूर्वक योग मार्ग का पथिक बनकर, पांच यम और पांच नियमों का निष्ठापूर्वक पालन करते हुए, शुद्ध विवेक ज्ञान, शुद्ध निष्काम कर्म, शुद्ध निराकार ईश्वर की योगाभ्यास रीति से नित्य संध्या उपासना करेगा।

विशेष-उक्त शब्दावली की व्याख्या पतंजलि ऋषि कृत योग दर्शन और उसके व्यास भाष्य आधारित करनी होगी।

अंत में योग की परिभाष-

योग-चित्तवृत्तिनिरोधः।

(योग दर्शन1/2) योग-समाधि। (व्यास भाष्य) जिज्ञासु योग वेद साधक!

● दिलीप वेलाणी, मुंबई।

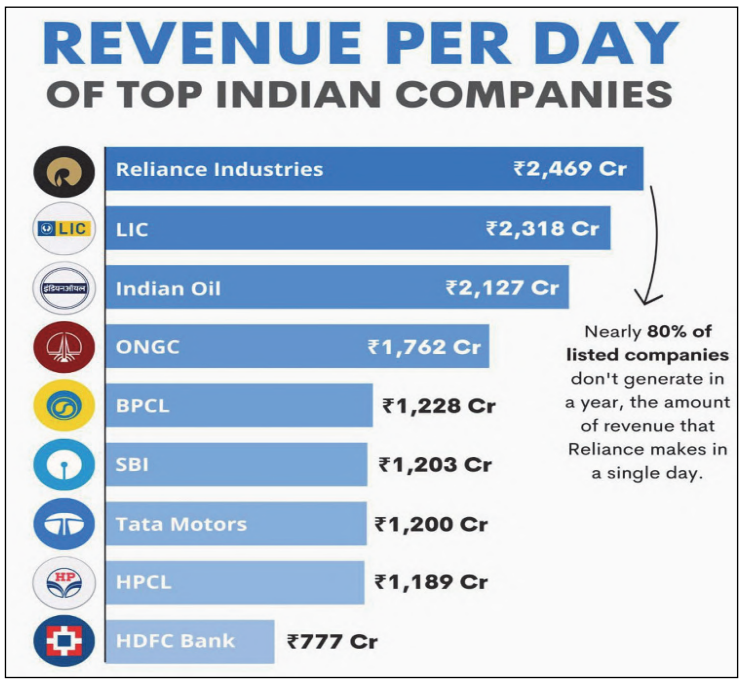

शीर्ष भारतीय कंपनियों का प्रतिदिन का राजस्व
(इन्फोग्राफिक क्रेडिट-इन्वेस्टीवाइज)

भारतीय बीमा नियामक IRDA ने Ulip यानी यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसीज को लेकर सख्त रवैया अपनाया है। नियामक ने बीमा कंपनियों को साफ-साफ कहा है कि वे विज्ञापनों में यूलिप को निवेश/इन्वेस्टमेंट की तरह दिखाना बंद करें। इसे लेकर नियामक ने हाल ही में एक मास्टर सर्कुलर जारी किया है।

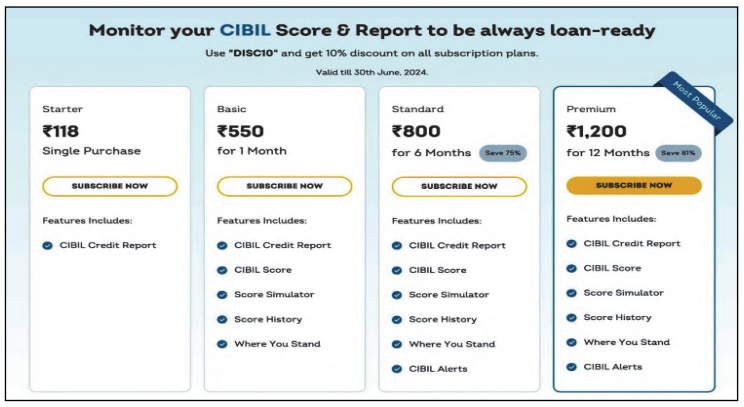

CIBIL118 में एक बार स्कोर रिफ्रेश करने का विकल्प देता है। यह कभी-कभार इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं या उन लोगों के लिए अच्छा है जिन्हें साल में सिर्फ दो बार ही अपना डेटा चेक करना होता है, जो कि ज़्यादातर लोगों के लिए काफी है। थर्ड-पार्टी ऐप्स को अपनी रिपोर्ट मुफ्त में एक्सेस करने देने के बजाय इस सेवा का इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है।

अब फोन कॉल आने पर फोन नंबर्स के साथ नाम भी आएगा, जिस नाम से SIM Card खरीदा है वह नाम डिस्प्ले होगा। भारत सरकार/दूरसंचार विभाग ने फ्रॉड रोकने और साइबर सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए सभी टेलिकॉम कंपनियों को यह निर्देश दिए है। नए निर्देश लागू करने हेतु संभावित तिथि 15 जुलाई 2024

आधार कार्ड फ्री अपडेशन

भारत सरकार ने आधार कार्ड को निःशुल्क अपडेट करने की समय-सीमा 14 सितंबर 2024 तक बढ़ा दी है। इस विस्तार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि निवासी बिना किसी शुल्क के अपनी आधार जानकारी को सटीक और अद्यतित रख सकें।

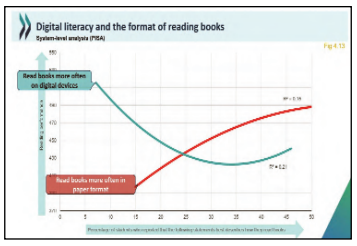

छात्रों की डिजिटल साक्षरता और उनके कागज या डिजिटल डिवाइस से पढ़ने के बीच सहसंबंध-स्रोत-OECD

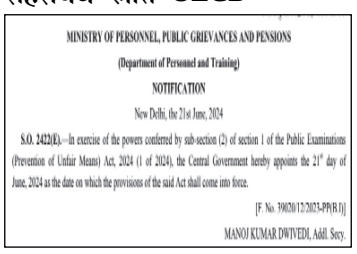

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS
(Department of Personnel and Training)
NOTIFICATION
New Delhi, the 21st June, 2024
S.O. 2422(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Act, 2024 (1 of 2024), the Central Government hereby appoints the 21st day of June, 2024 as the date on which the provisions of the said Act shall come into force.
[F. No. 390/20/12/2023-PP(R.I)]
MANOJ KUMAR DWIVEDI, Addl. Secy.

सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम आज (21 जून, 2024) से लागू हो गया है।

IAS-SS नकुल, वित्त मंत्री के PS नियुक्त किये गये। IRS विनय कुशल, मंत्री अश्विनी वैष्णव के PS नियुक्त किये गये। IFOS तखूत सिंह राणावत, मंत्री HD कुमारस्वामी के PS नियुक्त किये गये।

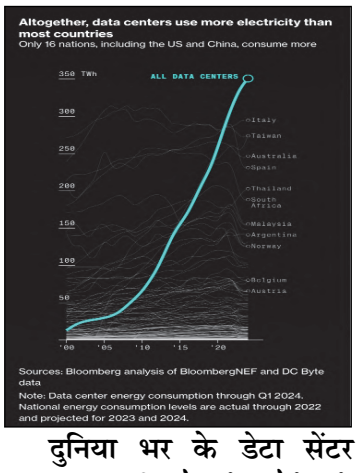

दुनिया भर के डेटा सेंटर मिलकर इटली और स्पेन जैसे बड़े देशों से भी ज्यादा बिजली का इस्तेमाल करते हैं।

पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कुशल भारतीयों के लिए वीजा के बारे में पूछा।

उनका जवाब-यदि आप किसी कॉलेज से स्नातक हैं, तो मुझे लगता है कि आपको अपने डिप्लोमा के हिस्से के रूप में स्वचालित रूप से ग्रीन कार्ड मिलना चाहिए, ताकि आप इस देश में रह सकें।

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी
National Testing Agency
Excellence in Assessment
(उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त संगठन)
(An Autonomous Organization under the Department of Higher Education, Ministry of Education, Government of India)

PUBLIC NOTICE
21.06.2024

Postponement of the Joint CSIR-UGC-NET Examination June-2024

1. This is in continuation to the Public Notice dated 15.06.2024 vide which Advance Intimation of Examination City allotted to the applicants of the Joint CSIR-UGC-NET Examination June-2024 along with schedule of Examination was informed to all the candidates.
2. The candidates are hereby informed that the Joint CSIR-UGC-NET Examination June-2024 which was scheduled to be held between 25.06.2024 to 27.06.2024 is being postponed due to unavoidable circumstances as well as logistic issues. The revised schedule for the conduct of this examination will be announced later through the official website.
3. The Candidates are advised to keep visiting the official website: https://csirnet.nta.ac.in. for the latest updates.
4. For any queries or /clarifications, candidates can call NTA Help Desk at 011-40759000 or 011-69227700 write to NTA at csirnet@nta.ac.in.

Sd/-
Senior Director (NTA)

CSIR-UGC-NET परीक्षा अगले आदेशों तक स्थगित।

शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है

देश के सामर्थ्य के लिए शिक्षा का महत्व सभी जानते हैं, मानते हैं और बखानते हैं। समकालीन चर्चाओं में 'युवा भारत' की भूमिका सभी लोग दुहराते हैं और डेमोग्रेफिक डिविडेंड की बातें करते नहीं थकते। चुनावी घमासान में सबने एक स्वर से देश को आगे ले जाने की क़समें खाईं थीं किंतु शिक्षा की प्रासंगिकता तथा रोज़गार के लिए शिक्षा के महत्व को लेकर लगभग सभी मौन ही धारण किए रहे। वे इसकी स्थिति से से संतुष्ट थे या फिर थक हार कर यह मान चुके हैं कि इस सिलसिले में कुछ भी मुमकिन नहीं है। मंहगाई, बेरोजगारी, आरक्षण की सख़्त ज़रूरत, पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते और भारतीय संविधान की सुरक्षा जैसे भारी भरकम मुद्दों के बीच शिक्षा और संस्कृति से जुड़े सवाल लगभग नदारद थे।

घोषणा-पत्र, संकल्प-सूची और गारंटियों की काकली के बीच शिक्षा द्वारा मनुष्य के निर्माण और उसके संवर्धन और संरक्षण से जुड़े प्रश्न की कोई जगह नहीं थी। सभी नेता मौखिक रूप से देश को बचाने, बनाने, समता लाने तथा सबको सुखी बनाने के लिए तैयार थे। सभी नेता बढ़-चढ़ कर गरीबों को अनाज देने, मुफ़्त रुपये बाँटने और सभी तरह की भौतिक सुविधाएँ जुटाने की घोषणा करने और खटाखट ख़ैरात बाँटने को तैयार थे, यह जान कर भी कि सरकार के पास कोई जादुई तिजोरी नहीं है कि फटाफट सब कुछ सब को मुहैया कर दिया जाये । वे यह भी नहीं सोच रहे थे कि सार्वजनिक मुफ़्तखोरी की लत का नुक़सान सबको भुगतना पड़ेगा। आख़िर अकर्मण्य बनाने में किसका भला होगा? मनुष्य बनने लिए संस्कार की आवश्यकता पड़ती है। यही समझ कर शिक्षा की संस्थाएँ बनी। भारत इस तरह के प्रयास में अग्रगण्य था। यहाँ के नालंदा और तक्षशिला के बहु अनुशासनात्मक और समावेशी विश्वस्तरीय विश्वविद्यालय संसार में कहीं न थे। औपनिवेशिक दौर में शिक्षा की जो व्यवस्था रोपी गई उसके फलस्वरूप हम जिस तरह पिछड़े उससे अभी तक उबर न सके। यह बिडम्बना ही कही जाएगी कि विकसित भारत का नारा देते हुए आज देश में शिक्षा आज कई तरह की दुर्दशाओं के दौर से गुजर रही है।

यह एक दुखद सत्य है कि स्वतंत्र भारत में चर्चाएँ होती रहीं, आयोग बनते रहे, शोध रपटें आती रहीं, योजनाओं का खाका भी बनता रहा, कुछ आधे-अधूरे कदम भी उठाए गए परंतु कभी भी शिक्षा की ओर समग्रता से तथा व्यावहारिक स्तर पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया जा सका था। इसके लिए ढुलमिल और टालू नज़रिया ही अपनाया जाता रहा।

मोदी सरकार के पहले दौर से ही वर्ष 2015 में शिक्षा में सुधार का वादा ही नहीं किया गया बल्कि बल्कि नई शिक्षा नीति का बनाने की क़वायद भी शुरू की। सांकेतिक पहल के रूप में 'मानव संसाधन मंत्रालय' का नाम 'शिक्षा मंत्रालय' कर दिया गया था। दूसरे कार्यकाल में अपनी प्रतिबद्धता दिखाते हुए सरकार ने 2020 में अंतरिक्ष विज्ञानी डा कस्तूरीरंगन की अगुआई में लम्बे सलाह-मशविरे के बाद नई शिक्षा नीति आई। सबको आशा बंधी कि शिक्षा में एक नया सबेरा आने वाला है । उसकी कुछ झलक भी मिली थी पर अभी भी लम्बी दूरी तय करना शेष है। अब 2024 में मोदी सरकार की 71 मंत्रियों की फ़ौज के साथ तीसरी पारी सौदिनी एजेंडे के साथ शुरू हो चुकी है। शिक्षा के लिए उसमें क्या जगह है यह तो स्पष्ट रूप से पता नहीं पर पुराने शिक्षा मंत्री ही फिर से दायित्व सँभाल रहे हैं और विभाग का काम-धाम रूटीन में पहले जैसा ही चलता रहेगा ।

याद रहे कि शिक्षा नीति-2020 कक्षा तीन से लेकर स्नातकोत्तर स्तर तक की शिक्षा में 'आमूल-चूल परिवर्तन' लाने की विशाल महत्वाकांक्षा के साथ आगे बढ़ी थी। इस नीति को लागू करने की योजना पर खंड-खंड में कुछ काम भी शुरू हुआ। कुछ समितियाँ बनीं, कुछ गोष्ठियाँ भी हुईं और साथ में अनेक स्तरों पर और विभिन्न समूहों के साथ विचार-विमर्श भी चलता रहा। नीति की आत्मा को समझ कर नियमों और व्यवस्थाओं में फेर-बदल भी हुए थे। कई परिवर्तन कुछ जगहों पर लागू हो चुके हैं। पर प्रगति देखते हुए यही लगता है कि रस्म अदायगी ही हो रही है। आधे-अधूरे ढंग से धीमी गति से इस पर काम चल रहा है। शिक्षा के संचालन में विकल्पों की व्यवस्था, रुख़ में लचीलापन, व्यवस्था की सहजता, स्थानीयता पर बल, पारिस्थितिकी की चिंता, संस्कृति के साथ जुड़ाव, कुशलता-निर्माण को महत्व, रोज़गार की उन्मुखता और शिक्षा देने में मातृभाषा के अधिकाधिक उपयोग की बात लिखित और मौखिक रूप में बार-बार सरकारी तंत्र द्वारा दुहराई जाती रही है। ये संकल्प जितने आकर्षक हैं उनको लागू करना उतना ही कठिन है। परिणाम है कि पहले की तुलना में परिसरों में दुर्व्यवस्था बढ़ती जा रही है और अध्ययन, अध्यापन तथा शोध की गुणवत्ता में गीयवत दर्ज हो रही है। आज शिक्षा के ज़्यादातर परिसर सिर्फ़ प्रवेश लेकर परीक्षा करा रहे हैं और डिग्री देने में व्यस्त हैं। साल में दो बार प्रवेश की ताजी योजना शिक्षा संस्थाओं को और व्यस्त करने वाला होगा। शिक्षा का सम्पादन दिनों-दिन कमजोर होता जा रहा है। ख़ास तौर पर स्कूली शिक्षा की स्थिति पूरे देश में ख़स्ता हाल हो रही है। नीति-हीनता की विपत्ति यह है कि शिक्षक-प्रशिक्षण की व्यवस्था क्या हो? उसका पाठ्यक्रम कैसा हो ? और कितने समय में उसे कैसे किया जाये?

आदि प्रश्नों को लेकर कोई स्पष्ट और दृढ़ व्यवस्था नहीं हो पाई है और किस्म-किस्म के संशय बरकरार हैं। शिक्षा के जमीनी हालात चिंताजनक हो रहे हैं और कोई उसका पुरसाहाल लेने वाला नहीं है। कागज़-पत्र की कार्रवाई बेशक खास हो रही है। नैक है, एनआईआरएफ है, यूजीसी है और और भी बहुत कुछ है पर शिक्षा जगत में संसाधनों का घोर अकाल पड़ा है। उस स्थिति में 'आनलाइन' एक बड़ा सहारा बन कर अवतरित हुआ है। अब प्रवेश, पढ़ाई, परीक्षा और अनुसंधान सब काम इसकी बदौलत चल पड़ा है। गुरु-शिष्य संबंध और शिक्षा के साक्षात् सजीव अनुभव अब इतिहास की बात होती जा रही है। नीट आदि हर तरह की परीक्षा में पेपर लीक होना, परीक्षा परिणाम में धांधली और मानकों को धता बताना आम बात हो रही है। प्राइमरी से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक लगभग सभी संस्थाओं में अध्यापकों की कमी बनी हुई है। जहां नियुक्ति हो रही है वहाँ किस तरह की धांधली होती है यह बंगाल के उदाहरण से बख़ूबी से समझी जा सकती है जो पकड़ में आकर सार्वजनिक हो चुका है। प्राचार्य और कुलपति आदि उच्च पदों को लेकर भी नाना प्रकार के संशय की गहरी छाया बनी हुई है। आर्थिक अपराध, चारित्रिक विचलन, नियमों की अवहेलना और साहित्यिक चोरी जैसी दुर्घटनाएँ शैक्षिक परिसरों में तेज़ी बढ़ रही हैं। बहुत से कुलगुरुओं को पद से हटाना पड़ा और बहुत से आरोपित हैं। शिक्षा की पवित्र संस्कृति लुप्त होती जा रही है। यहाँ भी बाजार के तर्ज पर ही फायदे का सौदा और ख़रीद फरोख्त चलता है।

शिक्षा और परीक्षा की गुणवत्ता के साथ समझौता किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। दुर्भाग्य से माँग के अनुसार स्तरीय शिक्षा देने में हम लोग पिछड़ते गये और शैक्षिक संस्थाओं की व्यवस्था में निजीकरण छाता गया। सरकारी संस्थाओं की बदहाली के बीच निजी संस्थाओं की बाढ़ आ गई है। वे फल फूल रहे हैं और मनमानी फ़ीस वसूल रहे हैं। कोचिंग, ट्यूशन भी बड़े विशाल पैमाने पर शुरू हुई।

अब साल्वर गैंग शिक्षण और परीक्षा को प्रदूषित कर रहा है । परीक्षाओं में बहु विकल्पों वाले सवाल चल रहे हैं जिनके लिए रटने पर जोर है। नेट की परीक्षा जो अध्यापक के चुनाव की है उसमें अभिव्यक्ति, विवेचन और समीक्षा की क्षमता जाँचने की जगह बहु विकल्प के प्रश्न दिए जा रहे हैं। इन सबसे जरूरी क्षमता का ठीक ठीक आकलन नहीं हो पाता। एन टी ए सरकार के निर्देशन में सिर्फ़ कामचलाऊ तर्ज पर ठेके पर कार्य कर रही थी। फलत- नाजायज़ तरीक़ों से कमाई करने वाले जगह-जगह से उसमें सेंध लगा रहे थे जिसका ख़ामियाज़ा छात्र छात्राओं और उनके अभिभावकों को भुगतना पड़ रहा है। उनके परिश्रम, समय और आर्थिक नुक़सान की चिंता किसी को नहीं है। एनटीए के डीजी को बदल देना और व्यवस्था में चौकसी के लिए कानून पास करना नाकाफी है।

ट्रेडिंग और निवेश की दुनिया में, बाजार की अप्रत्याशित गतिविधियों से अभिभूत होना आसान है। डॉ. एलेक्जेंडर एल्डर की समझदारी हमें याद दिलाती है कि भले ही हम बाजार को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन हम हमेशा अपने कार्यों और प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। बाजार में प्रभावी ढंग से नेविगेट करने के लिए अपनी रणनीतियों, अनुशासन और निरंतर सीखने पर ध्यान केंद्रित करें।

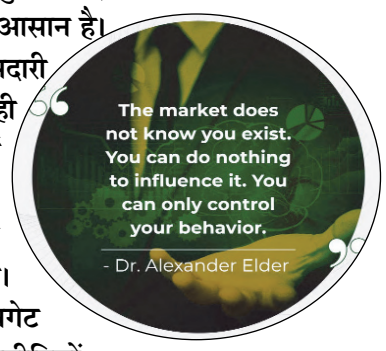

MeitY ने फेलोशिप के लिए AI स्कॉलर्स को नामांकित करने के लिए शीर्ष संस्थानों को आमंत्रित किया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रोजेक्ट करने वाले छात्रों के लिए IIT, NIT आदि सहित 50 संस्थानों से नामांकन आमंत्रित करके 10,372 करोड़ रुपये के इंडियाएआई मिशन की शुरुआत की है। बी.टेक छात्र 3 किस्तों में 1 लाख रुपये एम.टेक छात्र 4 किस्तों में 2 लाख रुपये रुपये की धनराशि प्रदान करेगा।

फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन-ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम (FTI-TTP) गृह मंत्रालय ने पूर्व-सत्यापित भारतीय नागरिकों और OCI कार्डधारकों के लिए फास्ट-ट्रैक इमिग्रेशन को सक्षम करने के लिए कार्यक्रम शुरू किया है। भारतीय नागरिक 2000 रुपये (नाबालिगों के लिए 1000 रुपये) और OCI के लिए 100 डॉलर का शुल्क देकर 'फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन-ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम' के लिए साइन अप कर सकते हैं।

ब्रिटेन के सबसे अमीर परिवार के चार सदस्यों प्रकाश हिंदुजा, उनकी पत्नी कमल हिंदुजा, उनके बेटे अजय हिंदुजा और उनकी पत्नी नम्रता हिंदुजा को भारतीय प्रवासी नौकरों का शोषण करने के आरोप में स्विस कोर्ट ने जेल की सजा सुनाई है। इन नौकरों से वे 700 रुपये (7) प्रतिदिन से भी कम पर 18 घंटे तक काम करवाते थे। स्विट्जरलैंड में प्रति घंटे की दर 32chf है जो 2800 रुपये (£w}) है। उन्होंने उन्हें स्थानीय मुद्रा के बजाय भारतीय रुपये में भुगतान किया। उनके पासपोर्ट जब्त कर लिए और उन्हें बाहर जाने की अनुमति नहीं दी। उन्होंने अपने नौकरों को उचित वेतन देने की तुलना में अपने कुत्तों की देखभाल में अधिक पैसा खर्च किया।

तीसरे कार्यकाल में तीन गुना बेहतर तरीके से चलाएंगे सरकार-मोदी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18वीं लोकसभा की कार्यवाही शुरु होने से पहले आज चुनकर आये सांसदों का अभिवादन करते हए सभी से जनता की आकांक्षाओं पर खरा उतरने का आग्रह किया और कहा कि वह सबकी सहमति से सरकार चलाएंगे इसलिए उन्हें उम्मीद है कि विपक्ष जिम्मेदारी से काम कर जन भावनाओं पर खरा उतरेगा।

श्री मोदी ने संसद भवन परिसर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा देश के 65 करोड़ लोगों ने 18वीं लोकसभा के प्रतिनिधियों को आकांक्षाओं के साथ चुनकर भेजा है। जनता ने जो भरोसा जताया है , हम सबको मिलकर उनकी आकांक्षाओं पर खरा उतारना होगा। उन्होंने विश्वास दिलाया कि वह सबकी सहमति से सरकार चलाएंगे और विपक्षी दलों से उम्मीद जताई है कि वे भी जनता की आकांक्षाओं पर खरा उतर कर काम करेंगे। उन्होंने कहा संसदीय लोकतंत्र में आज का दिन गौरव का दिन है। आजादी के बाद पहली बार हम अपने बनाये नये संसद भवन में शपथ लेने जा रहे हैं। अब तक यह प्रक्रिया पुराने संसद भवन में हुआ करती थी। आज का दिन विशेष महत्वपूर्ण है और इस अवसर पर मैं सभी नवनिर्वाचित सांसदों का अभिनंदन करता हूं और सबको शुभकामनाएं देता हूं।

प्रधानमंत्री ने कहा, विकसित भारत 1947 जैसे कई संकल्पना को लेकर आज 18वीं लोकसभा का आरंभ हो रहा है। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का चुनाव बड़े शांत और गौरवपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ है। यह हम सबके लिए गौरव की बात है। करीब 65 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं ने चुनाव में हिस्सा लिया। उन्होंने 2024 के चुनाव को महत्वपूर्ण बताया और कहा, यह चुनाव महत्वपूर्ण है क्योंकि आजादी के बाद दूसरी बार किसी सरकार को लगातार तीसरी बार सेवा करने के लिए देश की जनता ने अवसर दिया है और यह अवसर लंबे समय बाद देश में आया है इसलिए यह सब हम सबके लिए गौरव का विषय है। जनता ने तीसरे कार्यकाल के लिए हमारी सरकार को मौका दिया और इसका मतलब है कि उन्होंने हमारे काम पर भरोसा किया है और उस पर मुहर लगाई है। इसके लिए मैं देशवासियों का आभार व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा देश चलाने के लिए सहमति होती है और सरकार बनाने के लिए बहुमत होता है इसलिए हमारा लक्ष्य है कि सबको साथ लेकर और सबकी सहमति से देश की जनता की सेवा करना है। देश के 140 करोड लोगों की आशा और आकांक्षाओं को पूरा करना है। हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं, सबको साथ संविधान की मर्यादाओं का पालन करते हुए विकास को गति देना चाहते हैं। यह खुशी की बात है कि 18वीं लोकसभा में युवा सांसदों की संख्या अच्छी खासी है।

आपातकाल को लोकतंत्र के लिए काला धब्बा बताते हुए उन्होंने कहा, जो लोग देश के संविधान के प्रति समर्पित हैं देश के लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए निष्ठावान है, उनके लिए 25 जून ना भूलने वाली तिथि है क्योंकि 25 जून को भारत के लोकतंत्र पर धब्बा लगा था, उसके 50 साल कल पूरे हो रहे हैं। भारत के लोग कभी नहीं भूलेंगे कि इस दिन लोकतंत्र को पूरी तरह से दबोच दिया गया था। आपातकाल देश के संविधान में काला धब्बा था। हम संकल्प करेंगे कि संविधान के अनुसार जन सामान्य के सपनों को पूरा करना है और अब कोई दूसरी बार कभी भी देश में दूसरा आपातकाल नहीं लग सकेगा। उन्होंने कहा देश की जनता ने तीसरी बार मौका दिया है। यह बहुत ही महान विजय है और अब हमारा दायित्व भी तीन गुना बढ़ गया है इसलिए देशवासी विश्वास दिलाता हूं कि हमारे पास दो बार सरकार चलाने का अनुभव है और हम पहले की अपेक्षा तीन गुना बेहतर सरकार चलाएंगे। श्री मोदी ने कहा, हम नए कार्यभार को लेकर आगे चल रहे हैं। सभी सांसदों से देश को बहुत अपेक्षा है इसलिए सबसे आग्रह करुंगा कि जनहित के लिए मील अवसर का उपयोग करें और हर संभव जनहित में कदम उठाएं।

प्रधानमंत्री ने विकसित दलों से भी जनहित के काम करने की अपील करते हुए कहा देश की जनता को विपक्ष से अच्छे कदमों की अपेक्षा हैं। अब तक उससे निराश मिली है लेकिन अब उम्मीद है कि विपक्ष जनता की आकांक्षाओं पर खराब उतरेगा।

उन्होंने उम्मीद जताते हुए कहा, देश को अच्छे और जिम्मेदार विपक्ष का आवश्यकता है और हमें विश्वास है कि 18वीं लोकसभा में जो सांसद जीत कर आए हैं वे लोगों की आकांक्षा को पूरा करेंगे। देश को आगे बढ़ने का हम सब का दायित्व है और हम सबको मिलकर जनता जे विश्वास पर खरा उतारते हुए आगे बढ़ाना है। देश के 25 करोड़ नागरिकों का गरीबी से बाहर निकलना नया विश्वास पैदा करता है और इससे यह भी विश्वास पैदा होता है कि जल्दी ही भारत को गरीबी से मुक्त करने में सफलता हासिल करेंगे। हमें उम्मीद है कि 18वीं लोकसभा संकल्प का सदन बनेगा ताकि सामान्य नागरिक के सपने साकार हो सभी सांसदों का स्वागत करता हूं अभिनंदन करता हूं और जो देश की जनता ने दायित्व दिया है उसे हम मिलकर के बखूबी निभाएं।

प्रधानमंत्री ने 18वीं लोकसभा को शुभ बताया और कहा हमारे यहां 18 अंक का बहुत मूल्य है। गीता के 18 अध्याय कर्म, कर्तव्य और करुणा का संदेश देते हैं। हमारे यहां पुराणों की संख्या भी 18 है। भारत के अमृत काल मे 18वीं लोकसभा का गठन शुभ संकेत है।

हेलो.....कंट्रोल रूम से निगम आयुक्त बोल रहा हूं, आपकी क्या समस्या है?

उज्जैन। नगर निगम आयुक्त श्री आशीष पाठक द्वारा नगर निगम के अधिकारियों के साथ ग्रांड होटल पर बाढ़ आपदा प्रबंधन को लेकर निगम द्वारा जो व्यवस्थाएं की गई है उसे लेकर समीक्षा बैठक करते हुए निर्देश दिए गए की बारिश के दौरान जिन क्षेत्रों में जल भराव की समस्या हो वहां पर प्रत्येक जोन के अनुसार राहत एवं बचाव कार्य समय से पूर्व सुनिश्चित रहे।

रात्रिकालीन में राहत एवं बचाव कार्य करना है तो इसके लिए बैकअप टीम एवं अतिरिक्त संसाधन एवं वाहनों की सुनिश्चितता रहे एवं सभी अधिकारी फील्ड में उपस्थित रहेंगे साथ ही निगम कंट्रोल रूम एक्टिव रहे एवं कर्मचारियों की संख्या बढ़ाते हुए कंट्रोल रूम में आने वाली शिकायतों का समाधान करें यह निर्देश निगम आयुक्त द्वारा दिए गए।

नगर निगम आयुक्त श्री आशीष पाठक द्वारा ग्रांड होटल पर बाढ़ आपदा एवं जल भराव की स्थिति को लेकर अधिकारियों के साथ निगम द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की गई आयुक्त द्वारा निर्देश दिए गए कि जल भराव एवं बाढ़ आपदा के दौरान निगम कंट्रोल रूम अपनी भूमिका तत्परता से निभाएं एवं सक्रिय रहे 24 घंटे कंट्रोल रूम पर कर्मचारी की उपस्थिति मय संसाधनों के साथ होना चाहिए,यदि आवश्यकता हो तो कंट्रोल रूम पर शिफ्ट के अनुसार कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जाए।

प्रत्येक जोन राहत एवं बचाव कार्य के दौरान समस्त उपकरणों की व्यवस्था की सुनिश्चितता रखें साथ ही रात्रि कालीन में बचाव एवं राहत कार्य के दौरान अतिरिक्त वाहन अतिरिक्त टीम,राहत एवं बचाव कार्य के दौरान धर्मशाला, सामुदायिक भवन को चिन्हित करना, जेसीबी, पोकलेन की व्यवस्था रखना एवं उपायुक्त, सहायक आयुक्त अपने जोन अंतर्गत अपने अधीनस्थों के साथ फील्ड में रहेंगे, निगम का उद्देश्य यही होना चाहिए की स्थिति कैसी भी हो निगम अमला फील्ड में तैनात रहे और किसी भी प्रकार की अपनी स्थिति ना बने।

निगम आयुक्त श्री आशीष पाठक द्वारा नगर निगम कंट्रोल रूम का औचक निरीक्षण करते हुए कंट्रोल रूम पर जो शिकायते प्राप्त होती है जो शिकायत रजिस्टर में दर्ज की जाती है

उसकी जानकारी प्राप्त की गई साथ ही पूछा कि रात को यदि राहत एवं बचाव कार्य की सूचना प्राप्त होती है तो क्या करोगे किस प्रकार से स्थिति से निपटा जाएगा यह सब व्यवस्था पूर्व से सुनिश्चित रखी जाए, किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल संबंधित शिकायत को संबंधित विभाग को हस्तांतरित करते हुए रिस्पांस करें, निरीक्षण के दौरान कंट्रोल रूम पर वार्ड क्रमांक 3 यादव नगर से श्री कुंदन माली द्वारा फोन लगाया गया जिस पर कमिश्नर ने फोन उठाते हुए संबंधित शिकायतकर्ता से बात की और कहा कि मैं निगम कमिश्नर बोल रहा हूं बताएं आपकी क्या शिकायत एवं समस्या है।

संबंधित द्वारा बताए गई शिकायत को रजिस्टर में दर्ज करते हुए शिकायत का निराकरण करने हेतु संबंधित विभाग को हस्तांतरित किया गया बैठक के पश्चात निगम आयुक्त द्वारा डूब प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया गया जिसके अंतर्गत शांति नगर,एकता नगर,सुदर्शन नगर वार्ड क्रमांक 54 अंतर्गत आने वाली विभिन्न कॉलोनी,शिव धाम कॉलोनी का निरीक्षण करते हुए रहवासियों से चर्चा की गई चर्चा के दौरान रहवासियों द्वारा बताया गया कि जब बारिश अत्यधिक होती है एवं क्षिप्रा नदी का जलस्तर बड़े पुल से ऊपर होता है तब निचले क्षेत्रों में जल भराव की स्थिति उत्पन्न होती है निगम आयुक्त द्वारा रह वासियों से चर्चा के दौरान पूछा कि निगम द्वारा बारिश से पूर्व नाले एवं नालियों की सफाई की है या नहीं तब रहवासियों द्वारा सही एवं सकारात्मक जवाब देते हुए कहा कि निगम द्वारा बारिश से पूर्व नाले एवं नालियों की सफाई की गई है एवं निगम अमला जल भराव के समय डूब प्रभावित क्षेत्रों में उपस्थित रहकर समस्त आवश्यक व्यवस्थाओं में जुटा रहता है।

मप्र और छत्तीसगढ़ संयुक्त रूप से सामाजिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम करें आयोजित-मुख्यमंत्री डॉ. यादव

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि पड़ौसी राज्य छत्तीसगढ़ की भौगोलिक सीमा के साथ-साथ दोनों राज्यों की साझा सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विरासत है। दोनों राज्यों की सरकारों द्वारा कुछ कार्यक्रम संयुक्त रूप से आयोजित किए जा सकते हैं। व्यवस्था और प्रबंधन की दृष्टि से दो राज्य बने हैं, पर भावनात्मक रूप से हम एक हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव छत्तीसगढ़ के उप-मुख्यमंत्री अरुण साव के साथ आए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रतिनिधिमंडल को समत्व भवन में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि दोनों राज्यों के जनप्रतिनिधि राष्ट्र निर्माण को समर्पित हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ के जनप्रतिनिधियों से मध्यप्रदेश के विकास और जनकल्याण के लिए सुझाव और सहयोग का आव्हान करते हुए उन्हें अपने ज्ञान और कौशल का मध्य प्रदेश में भी विस्तार करने के

लिए आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने उज्जैन के ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधियों को महाकालेश्वर के साथ-साथ उज्जैन स्थित भगवान श्रीकृष्ण परंपरा, देवी परंपरा के स्थानों एवं त्रिवेणी संग्रहालय के विभिन्न आयामों की जानकारी दी। कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ के उप-मुख्यमंत्री साव ने भी संबोधित किया।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संस्थापक शालिग्राम तोमर के भोपाल में आयोजित स्मृति समारोह में भाग लेने के लिए परिषद के लगभग 70 सदस्यों का दल छत्तीसगढ़ से भोपाल आया हुआ है।

दल ने मुख्यमंत्री डॉ. यादव को उनके छात्र जीवन से संबंधित छायाचित्र भेंट किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने छत्तीसगढ़ के उप-मुख्यमंत्री साव को अंग वस्त्रम, पुष्पगुच्छ व स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत किया साथ ही सदस्यों को भी अंग वस्त्रम भेंट कर अभिवादन किया। चंद्रहास चंद्राकर, विवेक सक्सेना और प्रदीप मिश्रा विशेष रूप से उपस्थित थे।

एमपी से जुड़े यूपी पेपर लीक मामले के तार, भोपाल की प्रिंटिंग प्रेस में छपे थे प्रश्न-पत्र

भोपाल। उत्तर प्रदेश में समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में एसटीएफ ने सोमवार को बड़ा खुलासा किया है। पेपर भोपाल की एक प्रिंटिंग प्रेस में छपे थे। इस मामले में यूपी एसटीएफ ने प्रिंटिंग प्रेस के मैकेनिकल इंजीनियर सुनील रघुवंशी समेत 6 लोगों को प्रयागराज से गिरफ्तार किया है। आरोपित सुनील ने पेपर लीक के एवज में दस लाख रुपये लिए थे। एसटीएफ की पूछताछ में सुनील ने बताया है कि दस लाख रुपए लेकर उसने पर्चा लीक किया था। प्रिंटिंग मशीन के पार्ट्स में खराबी बताकर उसने एक पुर्जे को निकाल लिया था। इसे रिपेयर कराने के नाम पर उसने पार्ट्स को बड़े बॉक्स में कागजों में लपेटकर पैक किया। इसी के बीच उसने मौका देखकर पेपर छिपा दिया था। इस तरह आसानी से वह पेपर को बाहर निकाल लाया था। इसके बाद उसने पेपर साथियों की मदद से लीक किया। प्रश्न पत्र लीक मामले में जिन आरोपितों को गिरफ्तारी हुई है उनमें सुनील रघुवंशी, भोपाल (मप्र), सुभाष प्रकाश, मधुबनी (बिहार), विशाल दुबे, प्रयागराज (यूपी), संदीप पाण्डेय,

प्रयागराज (यूपी), अमरजीत शर्मा, गया (बिहार), विवेक उपाध्याय, बलिया (यूपी) शामिल हैं। उत्तरप्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज ने 11 फरवरी 2024 को समीक्षा अधिकारी/सहायक समीक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक) परीक्षा-2023 का आयोजन किया था। इस परीक्षा के शुरू होने से पहले ही पेपर सोशल मीडिया पर वायरल होने की शिकायत मिली थी। जिसके बाद सरकार ने परीक्षा को निरस्त कर दी थी और यूपी एसटीएफ को इसकी जांच सौंपी थी।

भारत को बदनाम करने वाली और आपत्तिजनक रिपोर्ट

भारत में लोगों को खाने के लिए भोजन नहीं मिल रहा, लोग भूख से मर जाते हैं, कुपोषण के शिकार बच्चों की संख्या हजारों, लाखों में भी नहीं, करोड़ों में है। बच्चे पौष्टिक आहार नहीं मिलने से कई तरह की बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। यह कहना है भारत के संदर्भ में यूनिसेफ की ''चाइल्ड फूड पॉवर्टी'' रिपोर्ट का। यह रिपोर्ट कहती है, गंभीर बाल खाद्य गरीबी में रहने वाले बच्चों के मामले में भारत दुनिया के सबसे खराब देशों में शामिल है, जबकि उससे अच्छी स्थिति में पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका जैसे अनेकों देश हैं।

इससे पहले हमने देखा कि कैसे वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2023 में भारत को 125 देशों में से 111वें स्थान पर रखा गया था और दुनिया को यह बताने का प्रयास हुआ था कि भारत की रैंकिंग में गिरावट हो रही है। साल 2023 की सूची में 121 देशों की रैंकिंग में भारत 107वें नंबर पर था। 2021 में 101वें और 2020 में 94वें नंबर पर, किंतु वर्तमान में भारत की रैंकिंग चार पायदान और गिर गई है। यहां भारत से कई गुना अच्छी स्थिति में पाकिस्तान (102वें), बांग्लादेश (81वें), नेपाल (69वें) और श्रीलंका (60वें) नंबर पर दिखाया गया । ठीक इसी तरह से इस रिपोर्ट के माध्यम से यूनिसेफ ने भी यह बताने का प्रयास किया है कि भारत अपने बच्चों के बीच भोजन की गरीबी को दूर नहीं कर पा रहा । भारत को लेकर रिपोर्ट इसलिए भी चौंकाती है, क्योंकि भारत की करोड़ों की बाल जनसंख्या को इसमें समाहित कर दिया गया है। यूनिसेफ की पूरी रिपोर्ट के अध्ययन से जो निष्कर्ष निकलते हैं, वह यह हैं कि दक्षिण एशियाई देशों की सूची में भारत गंभीर बाल खाद्य गरीबी से जूझ रहा है यहां पांच वर्ष तक की आयु वाले 40 प्रतिशत तक बच्चे गंभीर बाल खाद्य गरीबी झेल रहे हैं । इसके अलावा 36 प्रतिशत बच्चे भारत में मध्यम बाल खाद्य गरीबी की चपेट में जीवन यापन करने को मजबूर हैं। यहां दोनों का योग किया जाए तब उस स्थिति में भारत में 76 प्रतिशत बच्चे उचित आहार के वंचित हैं। यहां दक्षिण एशियाई देशों की सूची में मुख्य तौर पर 07 देश शामिल किए गए हैं, जिनमें सिर्फ अफगानिस्तान को चाइल्ड फूड पॉवर्टी में भारत से पीछे रखा गया है, जबकि पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल समेत दुनिया के अनेकों देश भारत से बेहतर स्थिति में हैं। यदि हम इस रिपोर्ट को स्वीकार करेंगे तो भारत दुनिया के उन 10 देशों में शामिल हो जाता है, जहां बच्चों को जरूरी पोषक आहार नहीं मिल पाता। विश्व में सबसे ज्यादा स्थिति सोमालिया की खराब है, वहां 63 प्रतिशत बच्चों तक उचित आहार की पहुंच नहीं है। इस क्रम में सोमालिया के बाद नाम गिनी का है, 54 प्रतिशत बच्चे यहां सही आहार मिलने के इंतजार में हैं। फिर गिनी - बिसाऊ 53 प्रतिशत, अफगानिस्तान 49 प्रतिशत, सिएरा लियोन 47 प्रतिशत, इथियोपिया 46 प्रतिशत और लाइबेरिया 43 प्रतिशत, भारत 40 प्रतिशत, पाकिस्तान 38 प्रतिशत और मॉरिटानिया 38 प्रतिशत के साथ इस सूची में हैं। जिनके कि बच्चे आहार के मामले में बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहे हैं। किंतु यहां प्रश्न यह है, क्या यह भारत के संदर्भ में दिया गया प्रतिशत सही है? इस संबंध में गहराई से किए गए अध्ययन के बाद ध्यान में आता है कि जिस डेटा का उपयोग यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रेंस फ़ंड (यूनिसेफ) अपने दावों को पुख्ता करने के लिए कर रहा है, वर्तमान में उन तथ्यों की कोई सत्यता ही नहीं है। क्योंकि यूनिसेफ

यूनिसेफ की ये रिपोर्ट जिस राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों का हवाला दे रही है, तब से अब तक देशभर में बहुत अधिक परिवर्तन हो चुका है। भारत में हर क्षेत्र में बहुत तेजी के साथ विकास हो रहा है, तब कैसे यूनिसेफ की यह रिपोर्ट को सही माना जा सकता है? ऐसे में यहां स्पष्ट हो रहा है कि भारत को लेकर यूनिसेफ की जून-2024 ''चाइल्ड फूड पॉवर्टी'' रिपोर्ट आज भ्रामक तथ्य प्रस्तुत करती है। इसलिए यह जरूरी है कि भारत के संदर्भ में दिए गए आंकड़ों को संयुक्त राष्ट्र बाल कोष देरी किए बगैर सही करे।

भारत के संदर्भ में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस 4 और 5) का संदर्भ देता है। जबकि उसके द्वारा जारी किए गए आंकड़े एनएफएचएस 4 एवं 5 से मेल ही नहीं खाते। इसमें भी समझने वाली बात यह है कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस-4) के आंकड़े वर्ष 2015 में जारी हुए थे जोकि 2014 की भारत की स्थिति को दर्शाते हैं। इसी प्रकार से एनएफएचएस-5 के आंकड़े 2020-21 के हैं। जबकि यूनिसेफ की यह ''चाइल्ड फूड पॉवर्टी'' रिपोर्ट इसी माह जून 2024 में प्रकाशित की गई है। अब इसमें सबसे बड़ा विरोधाभास यह है कि एनएफएचएस के अंतिम आंकड़े वर्ष 2020-21के जो प्रस्तुत किए गए हैं। इस रिपोर्ट में साफ लिखा हुआ है ''पिछले चार वर्षों से भारत में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में स्टंटिंग का स्तर 38 से 36 प्रतिशत तक मामूली रूप से कम हो गया है। 2019-21 में शहरी क्षेत्रों (30%) की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों (37%) के बच्चों में स्टंटिंग अधिक है। स्टंटिंग में भिन्नता पुडुचेरी में सबसे कम (20%) और मेघालय में सबसे ज्यादा (47%) है। हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और सिक्किम (प्रत्येक में 7 प्रतिशत अंक), झारखंड, मध्य प्रदेश और मणिपुर (प्रत्येक में 6 प्रतिशत अंक), और चंडीगढ़ और बिहार (प्रत्येक में 5 प्रतिशत अंक) में स्टंटिंग में उल्लेखनीय कमी देखी गई।'' अब यदि एक बार को यह मान भी लिया जाए कि संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ) भारत सरकार के इसी स्टंटिंग आंकड़ों का हवाला देते हुए अपने तथ्य प्रस्तुत कर रहा है। तब भी आप देख सकते हैं कि भारत में कहीं भी गंभीर बाल खाद्य गरीबी की श्रेणी में 40 प्रतिशत तक और 36 प्रतिशत मध्यम बाल खाद्य गरीबी की चपेट में बच्चे अपना जीवन यापन करते हुए नहीं दिखाई देते हैं । जिसमें कि दोनों का योग करने पर 76 प्रतिशत बच्चे देश के किसी भी कोने में खाद्य गरीब झेलते हुए नहीं मिलते।

इसके अनुसार अध्ययन के लिए उदाहरण के लिए दिल्ली को देखें, यहां की जनसंख्या 02 करोड़ है, तब उस स्थिति में 0 से 5 वर्ष की आयु वाले बच्चों की जो 10 प्रतिशत जनसंख्या 20 लाख है, उसका 76 प्रतिशत यानी इन बच्चों की बीस लाख की जनसंख्या में 15 लाख से अधिक संख्या में अकेले बच्चे देश की राजधानी में फूड पॉवर्टी के संकट से हर रोज गुजर रहे हैं। क्या वाकई अकेले दिल्ली जैसे महानगर में पंद्रह लाख से अधिक बच्चे भोजन के लिए तरसते एवं परेशानी में आज आपको मिलेंगे? इसी तरह से भारत के प्रत्येक नगर, महानगर, तहसील एवं ग्रामीण क्षेत्र का डेटा निकाला जा सकता है और यूनिसेफ के दिए आंकड़ों से तुलना की जा सकती है।

समय से आगे की सोच रखते थे डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी

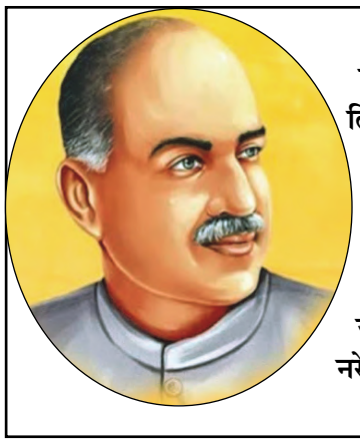

(डॉ. मोहन यादव)

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भारतीय राजनीति और समाज में उनके दूरदर्शी दृष्टिकोण और समय से आगे की सोच के लिए जाना जाता है। उनके जीवन और कार्यों ने दिखाया कि वे न केवल अपने समय के मुद्दों को समझते थे, बल्कि भविष्य की चुनौतियों और अवसरों का भी गहरा ज्ञान रखते थे। देश और समाज के लिए तुष्टिकरण की राजनीति कितना नुकसान पहुंचा सकती है, इसको हमारे कई दार्शनिक समाजसेवियों ने दशकों पहले समझ लिया था। एक देश और एक विधान का मंत्र देने वाले डॉ. श्याम प्रसाद मुखर्जी ने इसके लिए मिसाल पेश की। स्वतंत्र भारत की पहली सरकार ने तुष्टिकरण की नीति पर चलना शुरू किया तो डॉ. मुखर्जी ने कैबिनेट से इस्तीफा देकर भारतीय जनसंघ की स्थापना की। आज केंद्र में भाजपा की लगातार तीसरी बार सरकार बनी है और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में देश की बागडोर है। इसके पीछे डॉ. मुखर्जी की ही नीति और सोच है। आज उनका बलिदान दिवस है। हम और आप उन्हें अपने अपने तरीके से श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं।

हमें पता है कि आजादी मिलने के बाद बनी पहली केंद्र सरकार से डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के मतभेद देखने को मिले थे, जब तत्कालीन नेहरू सरकार ने भारत के संविधान में जबरन अनुच्छेद 370 जोड़कर देश की संप्रभुता और सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास किया था। अखंड भारत के समर्थक डॉ. मुखर्जी ने कांग्रेस की तुष्टीकरण नीति का विरोध किया।

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारत माता के महान सपूत थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें अंतरिम सरकार में उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री के रूप में शामिल किया। नेहरू और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली के बीच हुए समझौते के पश्चात 6 अप्रैल 1950 को उन्होंने मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर-संघचालक गुरु गोलवलकर जी से परामर्श लेकर श्री मुखर्जी ने 21 अक्टूबर 1951 को राष्ट्रीय जनसंघ की स्थापना की। 1951-52 के आम चुनावों में राष्ट्रीय जनसंघ के तीन सांसद चुने गए जिनमें एक डॉ. मुखर्जी भी थे। तत्पश्चात उन्होंने संसद के अन्दर 32 लोकसभा और 10 राज्यसभा सांसदों के सहयोग से नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किया। डॉ. मुखर्जी भारत की अखंडता और कश्मीर के विलय के दृढ़ समर्थक थे। उन्होंने अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को भारत के बाल्कनीकरण की संज्ञा दी थी। अनुच्छेद 370 के राष्ट्रघातक प्रावधानों को हटाने के लिए भारतीय जनसंघ ने हिन्दू महासभा और रामराज्य परिषद के साथ सत्याग्रह आरंभ किया। डॉ. मुखर्जी 11 मई 1953 को कुख्यात परमिट सिस्टम का उलंघन करके कश्मीर में प्रवेश करते हुए गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तारी के दौरान ही विषम परिस्थितियों में 23 जून, 1953 को उनका स्वर्गवास हो गया।

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जीवन और कार्य एक अद्वितीय उदाहरण है, जिसमें उन्होंने शिक्षा, राजनीति, और सामाजिक सुधार के विभिन्न मोर्चों पर उल्लेखनीय योगदान दिया। उनका जन्म 6 जुलाई 1901 को एक प्रतिष्ठित बंगाली भद्रलोक परिवार में हुआ था, जो उस समय अपनी बौद्धिकता और सांस्कृतिक योगदान के लिए विख्यात था।

मात्र 33 साल की उम्र में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कोलकता विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया। यह उनके ज्ञान, योग्यता और विद्वता का प्रमाण था। अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने विश्वविद्यालय में शैक्षिक सुधार किए, नई पाठ्यक्रम नीतियों को लागू किया और छात्रों के समग्र विकास पर जोर दिया।डॉ. मुखर्जी ने हिंदू महासभा के माध्यम से हिंदू समाज के अधिकारों और उनकी सुरक्षा के लिए जोरदार वकालत की। उन्होंने बंगाल के विभाजन के समय हिंदू बहुल क्षेत्रों को भारत में शामिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

हमें गर्व है कि हम सब उसी जनसंघ से निकले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक प्रखर शिक्षाविद, दृढ़ राजनीतिज्ञ और निष्ठावान राष्ट्रवादी थे। उन्होंने अपने जीवन के माध्यम से भारतीय समाज और राजनीति में अमूल्य योगदान दिया। उनके द्वारा स्थापित भारतीय जनसंघ ने भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया, और उनके विचार आज भी भारतीय जनता पार्टी और अन्य राष्ट्रवादी संगठनों में प्रतिबिंबित होते हैं। हमारे देश के लिए डॉ. मुखर्जी की प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। हमें माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का संसद में दिया गया वह वक्तव्य पूरी तरह याद है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नहीं होते, तो बंगाल भारत का हिस्सा नहीं होता। आज बंगाल अगर भारत में है तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कारण है।

राष्ट्र सेवा में स्वयं को समर्पित करने वाले मां भारती के अमर सपूत एवं जनसंघ के संस्थापक श्रद्धेय डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के राष्ट्र हित में किये गए कार्य एवं उनका आदर्श व्यक्तित्व हम सभी के लिए सदैव प्रेरणादायी रहेगा। राष्ट्र की अखंडता के लिए कंटकाकीर्ण मार्ग पर चलकर संगठन के एक-एक कार्यकर्ता को राष्ट्र प्रथम का मंत्र दिया। आज भाजपा के कार्यकर्ता वैभवशाली राष्ट्र निर्माण के लिए अहर्निश कार्य कर रहे हैं। डॉ. मुखर्जी की विचारधारा में देश की एकता-अखंडता, सांस्कृतिक उत्थान, देश के नागरिकों का आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक व राजनैतिक उत्थान समाहित हैं।

● डॉ. मोहन यादव
(लेखक म.प्र. के मुख्यमंत्री है)

उज्जैन-इंदौर के बीच मेट्रो

भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने उज्जैन और इंदौर को एक और बड़ी सौगात दे दी है। उज्जैन और इंदौर के बीच कनेक्टिविटी को लेकर मेट्रो ट्रेन की मंजूरी हो गई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ऐलान कर दिया है कि केंद्रीय मंत्री से उनकी बातचीत के दौरान प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। अब सिंहस्थ महापर्व के पहले उज्जैन और इंदौर के बीच मेट्रो ट्रेन दौड़ेगी। इस प्रोजेक्ट पर जल्द ही काम शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के कार्यकाल में उज्जैन-इंदौर सहित मध्य प्रदेश के सभी संभागों को रोज नई सौगात मिल रही है। मुख्यमंत्री ने अपने 200 दिन के कार्यकाल में मध्य प्रदेश को देश के नक्शे पर चमका दिया है। केंद्रीय नेतृत्व भी उनके कार्य से काफी खुश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद से मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव अब उज्जैन और इंदौर के बीच मेट्रो ट्रेन चलाने वाले हैं।

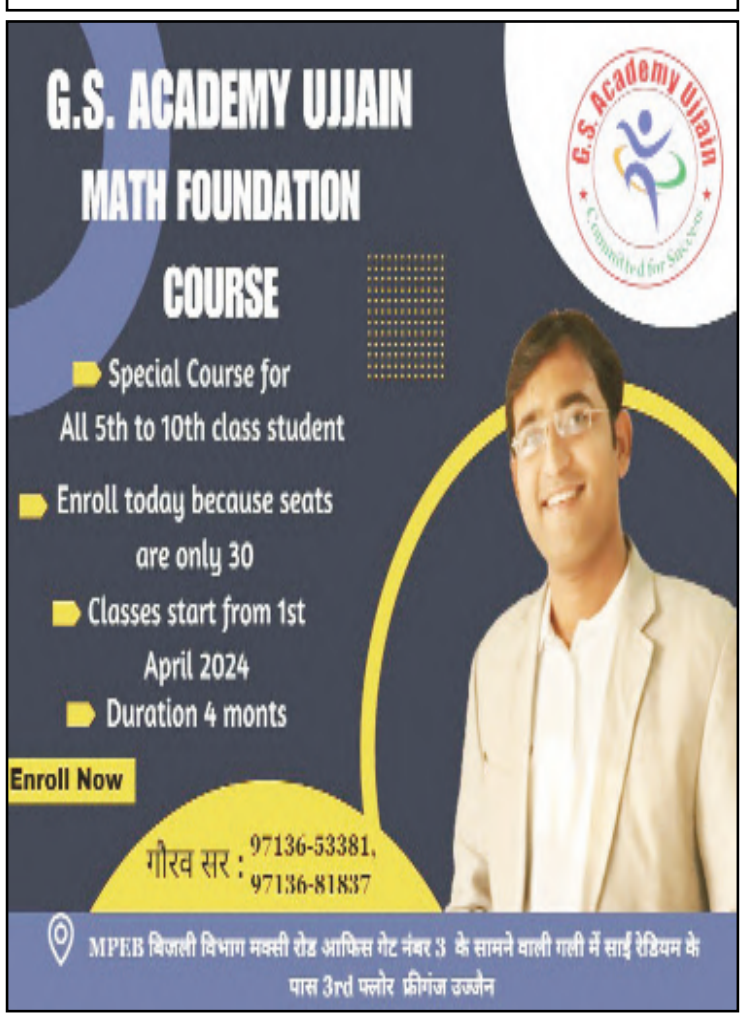

स्वताधिकारी/प्रकाशक मनमोहन शर्मा के लिये साप्ताहिक उज्जैन टाइम्स 110, तिरुपति एवेन्यू, होटल नत्रक्ष के पीछे, पंचक्रोशी मार्ग, उज्जैन (म.प्र.) से प्रकाशित एवं ज्योति ट्रेडर्स एवं प्रिन्टर्स न्यू रोड़, उज्जैन से मुद्रित।
● प्रधान सम्पादक : मनमोहन शर्मा मोबा. 9827233734 manmohan680@gmail.com (सभी वाद-विवादों का न्याय क्षेत्र उज्जैन रहेगा)। (म.प्र. शासन से 01-04-1997 से समाचार पत्र विज्ञापनों हेतु अनुमोदित)